रणजीत टाइम्स

इंदौर

बुधवार, 1 जुलाई, 2026

वर्ष 02 | अंक 158 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

मोदी-ट्रंप की दोस्ती का दिलचस्प खुलासा

सुबह 6 बजे फोन करना चाहते थे ट्रंप; व्यापार समझौते पर अंतिम मुहर की तैयारी

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही टैरिफ से जुड़ी खींचतान अब सुलझती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि यह समझौता केवल व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती नहीं देगा, बल्कि वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को भी और गहरा करेगा। इस बीच भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर एक दिलचस्प और अनसुना किस्सा सामने आया है, जिसने प्रधानमंत्री Narendra Modi और अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के व्यक्तिगत रिश्तों की गहराई को उजागर किया है।

भारत में अमेरिका के राजदूत Sergio Gor ने एक कार्यक्रम में दोनों नेताओं की दोस्ती से जुड़ा एक रोचक अनुभव साझा किया

उन्होंने बताया कि एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुबह-सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे। यह घटना दिखाती है कि दोनों नेताओं के बीच सिर्फ औपचारिक संबंध नहीं, बल्कि एक सहज और आत्मीय जुड़ाव भी है। यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के कार्यक्रम में बोलते हुए राजदूत गोर ने कहा कि कुछ महीने पहले वे मियामी में एक यूएफसी फाइट इवेंट के दौरान ट्रंप के साथ बैकस्टेज बैठे थे। उसी दौरान अचानक ट्रंप ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को फोन लगाया जाए। यह सुनकर गोर ने उन्हें याद दिलाया कि भारत में उस समय सुबह के लगभग 6 बज रहे होंगे और शायद यह कॉल के लिए बहुत जल्दी का समय होगा।

इस पर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मोदी जाग रहे होंगे

गोर के मुताबिक ट्रंप ने कहा था, "वह बिल्कुल मेरी तरह हैं, जल्दी उठते हैं, सोते नहीं।" यह टिप्पणी न सिर्फ दोनों नेताओं की दिनचर्या की समानता को दिखाती है, बल्कि उनके व्यक्तिगत तालमेल का भी संकेत देती है। हालांकि वह कॉल उसी वक्त नहीं हो पाई और अगले दिन बात हुई, लेकिन गोर ने कहा कि यह छोटी सी घटना बहुत कुछ कह जाती है।

उन्होंने कहा कि

जब दो नेताओं के बीच गहरी दोस्ती होती है तो औपचारिकताओं की दीवारें बहुत छोटी हो जाती हैं। हर बातचीत के लिए पहले से समय तय करना जरूरी नहीं रह जाता। राजदूत गोर ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के मन में भारत के लिए आज भी विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान भारत दौरे की यादों को अक्सर याद करते हैं। खासकर ह्यूस्टन में आयोजित Howdy Modi और अहमदाबाद में हुए Namaste Trump जैसे कार्यक्रमों ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दी थी।

गोर के अनुसार, ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भी भारत आने की इच्छा रखते हैं। यह संकेत इस बात का प्रतीक माना जा रहा है कि अमेरिका भारत को केवल एक रणनीतिक सहयोगी नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में टैरिफ को लेकर कई बार तनाव की स्थिति बनी थी। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ाए थे, जबकि भारत ने भी जवाबी कदम उठाए थे। लेकिन अब दोनों पक्ष इन विवादों को समाप्त कर एक व्यापक समझौते की ओर बढ़ते दिख रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है

कि यह समझौता आने वाले वर्षों में दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा देगा। व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना है। खासतौर पर टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका की साझेदारी वैश्विक संतुलन में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

राजदूत गोर ने कहा कि आने वाले दो वर्ष भारत-अमेरिका संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। उनका कहना था कि दोनों सरकारें सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि ठोस परिणामों पर भरोसा करती हैं। जो फैसले आज लिए जा रहे हैं, उनका असर आने वाले कई दशकों तक दिखाई देगा।

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियां वैश्विक राजनीति में भी अहम मानी जा रही हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव, इंडो-पैसिफिक रणनीति और वैश्विक व्यापारिक संतुलन के बीच दोनों देशों का सहयोग दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में मोदी और ट्रंप की व्यक्तिगत मित्रता और दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंध भविष्य की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर, एक तरफ जहां व्यापार समझौते की अंतिम तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर नेताओं के बीच की दोस्ती इन रिश्तों को और मजबूत आधार दे रही है।

मोदी 3.0 में बड़ा फेरबदल तय?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अगुवाई वाली मोदी 3.0 सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। दिल्ली के सत्ता गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार अपनी नई टीम का ऐलान कर सकती है।

राजनीतिक कैलेंडर पर नजर डालें तो 5 जुलाई और 11 जुलाई के बाद का समय कैबिनेट विस्तार के लिए अहम माना जा रहा है

प्रधानमंत्री मोदी का 6 से 11 जुलाई तक विदेश दौरा प्रस्तावित है। वहीं संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। ऐसे में 11 से 20 जुलाई के बीच फेरबदल की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। इससे पहले भी 2021 में मानसून सत्र से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था। इस बार फेरबदल केवल पदों की अदला-बदली तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि कई नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा है। साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री Pankaj Chaudhary का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वे उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और "एक व्यक्ति, एक पद" की नीति के चलते उनकी मंत्रिपरिषद से विदाई हो सकती है।

सूत्रों के मुताबिक इस बार कैबिनेट विस्तार में पिछड़ा वर्ग

महिलाएं और युवा सबसे ज्यादा फोकस में रहेंगे। भाजपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे चुनावी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है बताया जा रहा है कि 75 साल की उम्र के करीब पहुंच चुके कुछ वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी बदली जा सकती है। भाजपा का फोकस अब नई पीढ़ी को आगे लाने और चुनावी राज्यों में मजबूत सामाजिक संदेश देने पर है। इसमें "ईज ऑफ लिविंग" और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" जैसे सुधारों की समीक्षा होगी। माना जा रहा है कि मंत्रालयों के प्रदर्शन की यह समीक्षा भी मंत्रिमंडल फेरबदल का आधार बन सकती है।

पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, ड्राफ्ट बिल के लिए समिति गठित

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर ड्राफ्ट बिल राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए लागू किया जाएगा।

SIR पर INDIA गठबंधन का CJI को साझा पत्र
23 दलों ने उठाए चुनावी पारदर्शिता के सवाल

नई दिल्ली। बिहार में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर INDIA गठबंधन के 23 घटक दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को संयुक्त पत्र भेजा है।

गठबंधन ने पत्र में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि INDIA गठबंधन की 23 पार्टियां SURE (Secure, Unbiased, Reliable Elections) के सिद्धांत पर मजबूती से कायम हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची, चुनावी प्रक्रियाओं और निर्वाचन व्यवस्था

पर जनता का भरोसा बना रहना बेहद जरूरी है। ठबंधन ने अपने पत्र में आग्रह किया है कि चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण मामलों पर न्यायपालिका उचित संवैधानिक मार्गदर्शन दे, ताकि किसी भी मतदाता के अधिकारों का हनन न हो और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित हो।उधर, भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि मतदाता पुनरीक्षण जैसी प्रक्रियाएं संविधान और कानून के तहत नियमित प्रशासनिक कार्यवाही का हिस्सा हैं तथा इनका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। अब इस मुद्दे पर न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग की आगे की प्रतिक्रिया पर राजनीतिक हलकों की नजरें टिकी हुई हैं।

अंधेरी रात, ऊंची लहरें...
फिर भी नहीं हारी हिम्मत, कोस्ट गार्ड ने मौत के मुंह से बचाए 6 मछुआरे

मंगलुरु। कर्नाटक के मंगलुरु तट पर भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) ने खराब मौसम और समुद्र में उठती ऊंची लहरों के बीच साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर डूब रही नाव में फंसे छह मछुआरों की जान बचा ली। सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक ने अपना गश्ती पोत आईसीजीएस सचेत (ICGS Sachet) तत्काल रवाना किया। महज 90 मिनट में जहाज घटनास्थल पर पहुंच गया। उस समय समुद्र में तेज हवाएं, ऊंची लहरें, कम दृश्यता और घना अंधेरा राहत अभियान के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे।

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कोस्ट गार्ड की टीम ने सूझबूझ और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रिमोट-ऑपरेटेड लाइफबॉय की मदद से एक-एक कर सभी छह मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला और जहाज पर पहुंचाया। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मछुआरों को सुरक्षित स्थान पर लाया गया। भारतीय तटरक्षक बल की इस त्वरित कार्रवाई और पेशेवर दक्षता की व्यापक सराहना की जा रही है। एक बार फिर कोस्ट गार्ड ने साबित कर दिया कि समुद्र में संकट की घड़ी में वह हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

एपस्टीन विवाद की आंच गेट्स फाउंडेशन तक,
20 साल बाद वॉरेन बफेट ने रोका वार्षिक दान

न्यूयॉर्क। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने करीब 20 वर्षों में पहली बार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को अपना वार्षिक दान नहीं देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह निर्णय बिल गेट्स के दिवंगत यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े पुराने संबंधों की समीक्षा पूरी होने तक एहतियातन लिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, बफेट ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अतीत में गेट्स फाउंडेशन को दिए गए अपने दान को लेकर उन्हें कोई पछतावा नहीं है और वह उसे सही निर्णय मानते हैं। गौरतलब है कि वॉरेन बफेट वर्षों से गेट्स फाउंडेशन के सबसे बड़े दानदाताओं में रहे हैं। उनके इस कदम को परोपकारी जगत की बड़ी घटना माना जा रहा है। हालांकि, फाउंडेशन

की ओर से इस विषय पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर वैश्विक परोपकारी संस्थाओं और बड़े दानदाताओं की पारदर्शिता तथा जवाबदेही को लेकर चल रही बहस पर भी पड़ सकता है। फिलहाल, मामले से जुड़े तथ्यों की समीक्षा जारी है और आगे की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है।

कांगो के नाम भारत का दोस्ती संदेश
स्वतंत्रता दिवस पर जयशंकर ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वहां की सरकार और जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

डॉ. जयशंकर ने अपने संदेश में कहा कि भारत और कांगो के

संबंध आपसी विश्वास, सहयोग और साझा विकास पर आधारित हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। भारत अफ्रीका के देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को लगातार विस्तार दे रहा है और कांगो इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करते रहे हैं। गौरतलब है कि 30 जून को कांगो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस अवसर पर भारत ने कांगो की समृद्धि, शांति और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराया।

महापौर ने यातायात सुधार कार्यों की समीक्षा की, एमआर-04 रोड का नाम होगा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग

आदित्य शर्मा

इंदौर महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने यातायात विभाग की समीक्षा बैठक में शहर में चल रहे यातायात सुधार, चौराहा विकास, प्रतिमा स्थापना और पार्किंग व्यवस्थाओं की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने सिरपुर तालाब क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद प्रतिमा का लोकार्पण 11 सितंबर तक तथा अन्नपूर्णा रोड-सुदामा नगर मार्ग पर 16 अगस्त को 'अटल पथ' नामकरण एवं अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमा स्थल के भूमिपूजन की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में राजकुमार ब्रिज से बाणगंगा ब्रिज के मध्य निर्मित एमआर-04 रोड का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने पर चर्चा हुई। महापौर ने खालसा चौक, हाईकोर्ट चौराहा, सत्यसांई, इंद्रप्रस्थ सहित कई प्रमुख चौराहों पर यातायात सुधार, लेफ्ट टर्न निर्माण और बाधाओं को दूर करने के कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।

साथ ही शहर की विभिन्न पार्किंग व्यवस्थाओं की समीक्षा कर उनके नियमित एवं सुव्यवस्थित संचालन पर जोर दिया। वर्षाकाल के बाद प्रमुख चौराहों, मिडियन और रोटरी पर पेंटिंग, रोड मार्किंग एवं सौंदर्यीकरण कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश भी दिए।

सहजयोग ध्यान : साक्षी भाव और निर्विचारिता की सहज अवस्था

सहजयोग ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि चेतना की वह सहज अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह किसी मानसिक प्रयास, एकाग्रता या विचारों को दबाने का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मसाक्षात्कार के पश्चात् सहज रूप से प्राप्त होने वाली निर्विचार जागरूकता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्रार का द्वार खोलती है, तब विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगता है और साधक निर्विचार चेतना का अनुभव करता है। साक्षी भाव के अनेक लाभ हैं। इससे मन की चंचलता कम होती है, तनाव और चिंता घटती है, और व्यक्ति अधिक शांत, संतुलित तथा स्पष्ट दृष्टि वाला बनता है। साक्षी बनकर हम परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं, भावनाओं पर अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचते हैं, और संबंधों में धैर्य, करुणा तथा मधुरता विकसित होती है। यह आत्म-जागरूकता, आत्मविश्वास और आंतरिक स्थिरता को भी बढ़ाता है।

साक्षी भाव सहजयोग का आधार है। साक्षी बनकर हम अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और परिस्थितियों को केवल देखते हैं, उनसे तादात्म्य नहीं करते। इसी साक्षी भाव में मन शांत होता है, अहं और प्रतिअहं का प्रभाव क्षीण होने लगता है, और भीतर स्थित आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। उस समय ध्यान करना नहीं पड़ता, बल्कि ध्यान स्वयं घटित होता है। निर्विचार अवस्था ही वास्तविक स्वतंत्रता है। यही वह क्षण है जहाँ वर्तमान जीवंत हो उठता है, परमात्मा की चैतन्य शक्ति का अनुभव होता है और जीवन प्रेम, करुणा, शांति तथा आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सहजयोग का संदेश अत्यंत सरल है—अपने भीतर स्थित दिव्यता को जागृत कीजिए, साक्षी भाव में स्थित रहिए, और निर्विचार चेतना में परमात्मा के प्रेम एवं चैतन्य का निरंतर अनुभव कीजिए। यही सहजयोग है, यही आत्मसाक्षात्कार का सच्चा आनंद है। सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल-फ्री नंबर 1800-2700-800 अथवा www.sahajayoga.org.in से प्राप्त कर सकते हैं।

अवैध धारदार टडडरी चाकू के साथ युवक गिरफ्तार, छत्रीपुरा पुलिस की रेडो एरिया चेकिंग में बड़ी सफलता

खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। शहर में अपराध नियंत्रण और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना छत्रीपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रेडो एरिया चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध धारदार टडडरी चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देता, उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस आयुक्त संतोष सिंह के निर्देशन में शहरभर में रेडो एरिया एवं हॉट स्पॉट पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त जोन-4 सुनील मेहता, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दोशेष अग्रवाल एवं सहायक पुलिस आयुक्त विजय तिवारी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी।

चेकिंग के दौरान पुलिस को एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध धारदार टडडरी चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुरेन्द्र सिंह चौहान (27 वर्ष), निवासी पंचमूर्ति नगर, इंदौर बताया। आरोपी चाकू रखने का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 25(1-बी) के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक धर्मेन्द्र पाठक, आरक्षक धर्मेन्द्र सिंह, प्रमोद सिंह, अरुण सिंह चौहान, भूपेन्द्र सिंह एवं सैनिक स्वप्नेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

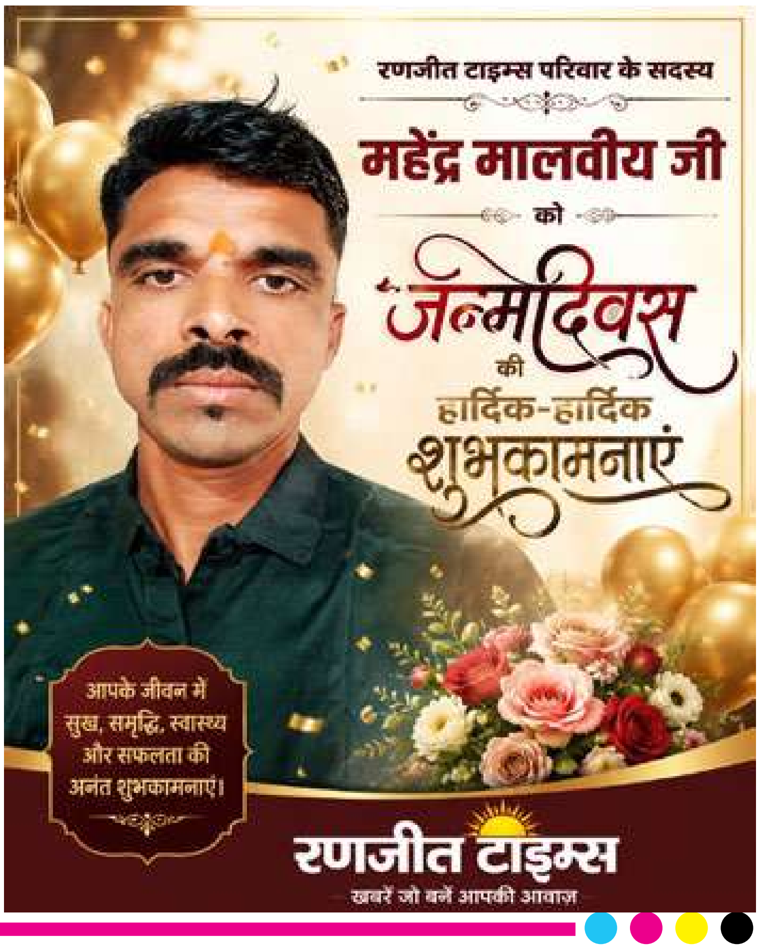

कांग्रेस की बैठक में उभरी अंदरूनी खींचतान, बड़े नेताओं की गैरमौजूदगी ने बढ़ाए सियासी

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आते दिखाई दिए। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) कार्यालय में मंगलवार को आयोजित पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को उजागर कर दिया। बैठक को आगामी राजनीतिक रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था, लेकिन इसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की गैरमौजूदगी ने नए राजनीतिक संकेत दे दिए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री Digvijaya Singh, पूर्व मुख्यमंत्री Kamal Nath और वरिष्ठ नेता Ajay Singh शामिल नहीं हुए। इन दिग्गज नेताओं की अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर असंतोष और गुटबाजी की चर्चाओं को और हवा दे दी है।

राजनीतिक गलियारों में इसे सिर्फ सामान्य अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा वीर भारत न्यास के मुद्दे को लेकर हुई। यह मामला पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर विवाद का कारण बना हुआ है। खासकर Digvijaya Singh और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Jitu Patwari के बीच इस विषय को लेकर सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती तल्खी अब संगठनात्मक बैठकों में भी साफ दिखाई देने लगी है।

बैठक में विधायक

Arif Masood और वरिष्ठ नेता Praveen Pathak ने जमीन से जुड़े विवाद को लेकर गंभीर सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने स्पष्ट कहा कि पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच सार्वजनिक मतभेदों से जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। उनका कहना था कि यदि कांग्रेस खुद अपने भीतर एकजुट नहीं दिखेगी तो जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है।

बैठक में यह सवाल भी प्रमुखता से उठा कि आखिर जमीन मामले में सच्चाई क्या है। नेताओं ने मांग की कि पार्टी नेतृत्व इस पूरे मामले में स्पष्टता लाए और यह तय करे कि किसका पक्ष सही है। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच हुए विवाद को लेकर लंबी चर्चा चली। कई नेताओं ने इसे संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया।

करीब कई घंटों तक चली इस बैठक में आखिरकार इस मुद्दे पर एक सामूहिक निर्णय लिया गया। तय किया गया कि जमीन विवाद और उससे जुड़े मामलों पर कांग्रेस आलाकमान यानी All India Congress Committee की लाइन के अनुसार आगे आंदोलन और रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर राजनीतिक रूप से मजबूती बनाने की कोशिश की जाएगी। बैठक में राम मंदिर चंदा चोरी के कथित मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बताते हुए इसके खिलाफ प्रदेशभर में प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की। पार्टी का मानना है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जा सकता है और जनता के बीच इसे प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक में बड़े नेताओं की गैरमौजूदगी केवल संयोग नहीं है। यह पार्टी के भीतर चल रहे शक्ति संतुलन और नेतृत्व संघर्ष का संकेत हो सकता है। खासकर ऐसे समय में जब मध्यप्रदेश में संगठन को मजबूत करने और भाजपा के खिलाफ आक्रामक रणनीति बनाने की जरूरत है, उस समय वरिष्ठ नेताओं की दूरी पार्टी के लिए चिंता का विषय बन सकती है।

कांग्रेस लंबे समय से मध्यप्रदेश में संगठनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है

विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जैसी महत्वपूर्ण बैठक में शीर्ष नेताओं की गैरहाजिरी ने इन सवालों को और मजबूत कर दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इन मतभेदों को किस तरह सुलझाती है और क्या कांग्रेस एकजुट होकर जनता के बीच अपनी रणनीति के साथ उतर पाएगी या नहीं। फिलहाल भोपाल में हुई यह बैठक एक बार फिर यह साबित कर गई है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है और अंदरूनी राजनीति का असर अब खुले मंचों तक पहुंच चुका है।

उज्जैन में 1.5 लाख हितग्राहियों की पेंशन तीन महीने से अटकी, 10 दिन में भुगतान का प्रशासन का दावा

उज्जैन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का इंतजार कर रहे करीब डेढ़ लाख हितग्राहियों के लिए राहत की खबर है। बुजुर्ग, दिव्यांगजन, विधवा, कल्याणी और अविवाहित महिला सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की पिछले तीन महीनों से अटकी पेंशन को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुसार, हितग्राहियों की ई-केवाईसी, आधार और समग्र आईडी की मैपिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। विभाग का दावा है कि यह प्रक्रिया अगले 10 दिनों में पूरी कर पात्र हितग्राहियों के खातों में लंबित पेंशन की राशि जारी कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक, तकनीकी कारणों और दस्तावेजों की मैपिंग पूरी नहीं होने से बड़ी संख्या में हितग्राहियों की पेंशन रुकी हुई है। इसके चलते कई बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने हितग्राहियों से अपील की है कि जिनकी ई-केवाईसी या अन्य आवश्यक औपचारिकताएं शेष हैं, वे जल्द से जल्द उन्हें पूरा कर लें, ताकि पेंशन जारी करने में कोई बाधा न आए। पेंशनधारकों को अब उम्मीद है कि प्रशासन अपने 10 दिन में भुगतान के दावे पर खरा उतरेगा और लंबे इंतजार के बाद उन्हें राहत मिलेगी।

ऑपरेशन 'अमिस्ताद' के तहत भारत ने वेनेजुएला में तेज़ किए राहत एवं बचाव कार्य

नई दिल्ली। भारत ने 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में राहत एवं बचाव अभियान को और तेज कर दिया है। भारतीय दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावित लोगों की मदद में जुटा है।

अधिकारियों के अनुसार, भारत ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक दवाइयां, खाद्य सामग्री, टेंट, कंबल और अन्य राहत सामग्री भेजी है। इसके साथ ही विशेष प्रशिक्षित एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) की टीम और चिकित्सा विशेषज्ञ भी राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

भारतीय दल प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, घायलों का उपचार करने और आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राहत सामग्री और विशेषज्ञ दल भी भेजे जाएंगे। भारत ने एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की घड़ी में मित्र देशों के साथ खड़े रहने की अपनी नीति को दोहराया है। 'ऑपरेशन अमिस्ताद' इसी मानवीय सहयोग और वैश्विक साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है। भारत ने वेनेजुएला की सरकार और जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हरसंभव सहायता जारी रखने का भरोसा दिलाया है।

मध्यप्रदेश में जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटल महाअभियान

इंदौर समेत 15 करोड़ दस्तावेज होंगे ऑनलाइन सुरक्षित

इंदौर। मध्यप्रदेश में जमीन से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित, पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बड़ा डिजिटल अभियान शुरू किया गया है। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में अब 15 करोड़ से अधिक भू-अभिलेखों और जमीनी रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। यह कार्य केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण योजना के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक और पारदर्शी बनाना है। इस अभियान से आने वाले समय में जमीन से जुड़े विवादों में कमी आने के साथ आम लोगों को रिकॉर्ड प्राप्त करने में भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य में पुलिस, प्रशासन, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और अन्य सरकारी विभाग पहले से ही अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के लाखों दस्तावेज

पहले ही डिजिटल किए जा चुके हैं। अब सबसे बड़ा फोकस राजस्व विभाग के भू-अभिलेखों पर है, जिन्हें व्यवस्थित रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है।

यह प्रक्रिया केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। बाद में 1 अप्रैल 2016 से इसे नए स्वरूप में पुनर्गठित कर डीआईएलआरएमपी (Digital India Land Records Modernization Programme) के तहत लागू किया गया। इस योजना का मकसद देशभर में भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और पुरानी मैनुअल व्यवस्था को डिजिटल सिस्टम में बदलना है। योजना के अंतर्गत मॉडर्न रिकॉर्ड रूम (एमआरआर) की अवधारणा तैयार की गई है, जिसके जरिए वर्षों पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित स्कैन कर डिजिटल फॉर्मेट में बदला जा रहा है। इससे दस्तावेजों के खराब होने, गुम होने या छेड़छाड़ की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाएगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर इन्हें ऑनलाइन तुरंत देखा और प्राप्त किया जा सकेगा।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक योजना के पहले चरण (2013 से 2020) में करीब 3 करोड़ 18 लाख 82 हजार 222 दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम पूरा किया गया था। इसके बाद दूसरे चरण (2021-22) में करीब 2 करोड़ 39 लाख 24 हजार 462 दस्तावेज डिजिटल किए गए। अब तीसरे और सबसे बड़े चरण में प्रदेशभर के 15 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए जिला स्तर पर अत्याधुनिक स्कैनिंग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। यहां पुराने कागजी रिकॉर्ड्स की सुरक्षित स्कैनिंग की जाएगी। इसके साथ प्रत्येक दस्तावेज का मेटाडाटा तैयार किया जाएगा ताकि भविष्य में रिकॉर्ड को आसानी से खोजा जा सके। भोपाल में इसके लिए डीबीईएस आधारित डबल-बाइंड डेटा एंट्री सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे डेटा की सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया में गुणवत्ता नियंत्रण को भी प्राथमिकता दी है। रिकॉर्ड स्कैनिंग और डेटा एंट्री के बाद संबंधित क्षेत्र के पटवारी ऑनलाइन गुणवत्ता परीक्षण करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कैन किया गया रिकॉर्ड और दर्ज की गई जानकारी पूरी तरह सही हो। सत्यापन के बाद ही रिकॉर्ड को अंतिम रूप दिया जाएगा। इन दस्तावेजों को अंतिम सत्यापन के बाद राज्य के Bhulekh Portal पर अपलोड किया जाएगा।

इंदौर निगम का बड़ा फैसला

ड्यूटी के दौरान हादसा होने पर सफाई मित्रों को मिलेगी 2.50 लाख तक आर्थिक सहायता

इंदौर। सफाई मित्रों की सुरक्षा और आर्थिक संबल को मजबूत करने के उद्देश्य से इंदौर नगर निगम ने नई आर्थिक सहायता योजना लागू की है। इस योजना के तहत ड्यूटी के दौरान दुर्घटना का शिकार होने वाले सफाईकर्मियों तथा ड्रेनेज-सीवरेज कर्मचारियों को हादसे की गंभीरता के आधार पर 25 हजार रुपये से लेकर 2.50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नगर निगम के अनुसार, योजना का उद्देश्य जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय पर आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। दुर्घटना की प्रकृति और चोट की गंभीरता के अनुसार सहायता राशि निर्धारित की जाएगी। इससे आकस्मिक संकट की स्थिति में कर्मचारियों को तत्काल राहत मिल सकेगी।

सफाई मित्र और सीवरेज कर्मचारी शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। कई बार उन्हें विषैली गैस, सीवर हादसों और अन्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह योजना उनके सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नगर निगम का कहना है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आर्थिक सहायता के साथ-साथ सुरक्षित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह पहल सफाईकर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के प्रति निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भूजल बचाने की सख्ती: नई कॉलोनियों में रिचार्ज प्वाइंट बिना नहीं मिलेगा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट

इंदौर। शहर में लगातार गिरते भूजल स्तर को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। तेजी से विकसित हो रही नई आवासीय कॉलोनियों के बीच जल संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब इंदौर में बनने वाली हर नई कॉलोनी में 20 से 25 फीट गहरे रिचार्ज प्वाइंट बनाना अनिवार्य होगा। इन रिचार्ज प्वाइंट्स की तकनीकी जांच और उनकी कार्यक्षमता की पुष्टि के बाद ही संबंधित कॉलोनी को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि यह कदम भविष्य में जल संकट को कम करने और भूजल स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

दरअसल, इंदौर शहर में लगातार नई कॉलोनियों का विस्तार हो रहा है। बड़ी संख्या में रिहायशी प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि यदि अभी से प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में शहर को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में प्रशासन ने नई कॉलोनियों में ओवरहेड वाटर टैंक के नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने के निर्देश भी जारी किए थे, ताकि पानी का बेहतर प्रबंधन हो सके। अब इस व्यवस्था को और मजबूत करते हुए वर्षा जल संरक्षण पर फोकस किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य यह है कि बारिश का अधिकतम पानी जमीन में समा सके और भूजल स्तर में सुधार हो।

कॉलोनी सेल प्रभारी अधिकारी रोशनी पाटीदार ने बताया कि शहर में तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। कई इलाकों में बोरवेल का जलस्तर पहले के मुकाबले काफी नीचे चला गया है। इसे रोकने के लिए हर नई कॉलोनी में रिचार्ज प्वाइंट बनवाने का फैसला किया गया है। इन प्वाइंट्स के जरिए बारिश का पानी सीधे जमीन के अंदर जाएगा और जलस्तर को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। अपर कलेक्टर Rinkesh Vaishya ने बताया कि वर्तमान में शहर में बारिश का बड़ा हिस्सा नालों और ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से बहकर निकल जाता है। इससे जमीन के भीतर पानी का पर्याप्त पुनर्भरण नहीं हो पाता। इसी समस्या के समाधान के लिए नई कॉलोनियों में 20 से 22 फीट या उससे अधिक गहराई वाले रिचार्ज प्वाइंट बनाए जाएंगे। इससे वर्षा जल सीधे जमीन में पहुंचेगा और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल एक औपचारिकता नहीं होगी। कई बार देखा गया है कि नियमों की पूर्ति केवल कागजों में दिखाई जाती है, लेकिन जमीन पर उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता नहीं होती। इस बार विभागीय अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर रिचार्ज प्वाइंट की गहराई, गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की जांच करेंगे। यदि निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया तो कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। इस फैसले का सीधा असर बिल्डरों और डेवलपर्स पर पड़ेगा। अब उन्हें अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग में जल संरक्षण की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देनी होगी। रिचार्ज प्वाइंट्स का निर्माण केवल अनुमति पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभावी रूप से काम करने वाला होना जरूरी होगा।

इससे निर्माण क्षेत्र में भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस तरह के उपाय प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं तो शहर में भूजल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इंदौर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है और ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज सिस्टम बेहद जरूरी हो गए हैं। प्रशासन का यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रणजीत टाइम्स 06
इंदौर, बुधवार 1 जुलाई 2026

एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की नजर

भरत तिवारी केस में CBI जांच और FIR की मांग पर आज सुनवाई

नई दिल्ली। बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। याचिका में मामले को कथित फर्जी मुठभेड़ बताते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की निगरानी में कराई जाए, ताकि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रहे। याचिका में कहा गया है कि ऐसे मामलों में कानून के शासन, मानवाधिकारों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र जांच अनिवार्य है। साथ ही, जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई पर कानूनी विशेषज्ञों और आम लोगों की नजरें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय कर सकता है कि जांच राज्य पुलिस के पास रहेगी या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाएगी। फिलहाल, मामले में किसी भी पक्ष की जिम्मेदारी या आरोपों की सत्यता पर अंतिम निर्णय आना बाकी है और अदालत की सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

राष्ट्रपति को मिली अफसरों को हटाने की ज्यादा ताकत

वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाते हुए उनके अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति नीति संबंधी मतभेद होने पर फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) के सदस्यों को पद से हटा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही FTC सदस्यों को 91 वर्षों से प्राप्त कानूनी संरक्षण प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। अब राष्ट्रपति को स्वतंत्र नियामक आयोगों के सदस्यों को हटाने के मामले में पहले की तुलना में अधिक अधिकार मिल गए हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति पद की कार्यकारी शक्तियों को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे भविष्य में अन्य स्वतंत्र संघीय एजेंसियों की स्वायत्तता और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर भी नई कानूनी बहस शुरू हो सकती है। वहीं, ट्रंप समर्थकों ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे प्रशासनिक जवाबदेही के लिए जरूरी बताया है, जबकि आलोचकों का कहना है कि इससे स्वतंत्र नियामक संस्थाओं की निष्पक्षता और स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। इस फैसले को अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था और कार्यपालिका की शक्तियों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में से एक माना जा रहा है।

केतन हत्याकांड में नया मोड़

'गेट टेस्ट' से जुड़ेगी जांच की कड़ी, 10 करोड़ के लीगल नोटिस से बढ़ा विवाद

पुणे। चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच और कानूनी लड़ाई दोनों नए दौर में पहुंच गई हैं। एक ओर पुलिस मुख्य आरोपी चेतन चौधरी की घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि के लिए उसका 'गेट एनालिसिस' (चाल की जांच) टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर मामले से जुड़े विवाद में एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया गोयल के भाई को 10 करोड़ रुपये का मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, गेट एनालिसिस टेस्ट के जरिए आरोपी की चाल और घटनास्थल पर उपलब्ध वीडियो फुटेज का वैज्ञानिक मिलान किया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि इससे जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकते हैं।

उधर, मामले में एक और विवाद तब खड़ा हो गया जब सिया गोयल के कथित रुख में बदलाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। इसके बाद एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले बयान दिए गए हैं और इसी आधार पर 10 करोड़ रुपये के मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा गया है। फिलहाल पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए वैज्ञानिक और डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगी है, जबकि मानहानि नोटिस से जुड़े विवाद का फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। मामले में जांच और न्यायिक कार्यवाही जारी है तथा किसी भी पक्ष के दावों की अंतिम पुष्टि अदालत और जांच के निष्कर्ष के बाद ही होगी।

ऑपरेशन 'सेफ क्लिक 2.0': खनियाधाना पुलिस ने रेड्डी चौराहा पर लगाया साइबर जागरूकता शिविर, डिजिटल अरेस्ट व OTP फ्रॉड से बचने के बताए उपाय

अतुल जैन

SP यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देश पर चला अभियान, निरीक्षक केदार सिंह यादव ने नागरिकों को किया सतर्क

खनियाधाना। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर प्रदेशभर में चलाए जा रहे साइबर सुरक्षा अभियान 'ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0' के तहत थाना खनियाधाना पुलिस द्वारा सोमवार 30 जून 2026 को रेड्डी चौराहा, पिछोर-चंदेरी रोड पर विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(प्रदेश स्तर से लेकर जोन तक मॉनिटरिंग)

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा एवं एडीजी साइबर तथा गुप्त वार्ता ए साई मनोहर के निर्देशन में संचालित इस अभियान के तहत

साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद कुमार सक्सेना एवं पुलिस उप महानिरीक्षक असित यादव द्वारा जोन स्तर पर साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए विशेष निर्देश जारी कर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

(शिवपुरी SP के निर्देश पर सक्रिय अभियान)

पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के मार्गदर्शन में जिले में साइबर जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एसडीओपी अनुभाग पिछोर प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक केदार सिंह यादव द्वारा रेड्डी चौराहा पर पहुंचकर आम नागरिकों, दुकानदारों एवं राहगीरों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

(इन अपराधों से किया सतर्क)

जागरूकता कार्यक्रम में निरीक्षक केदार सिंह यादव ने नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी KYC अपडेट के नाम पर ठगी, OTP शेयर कर खाते से पैसा निकालने, UPI फ्रॉड, लोन एप घोटाला एवं फर्जी निवेश योजनाओं में धोखाधड़ी के नए तरीकों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, बैंक खाता, एटीएम, पिन या OTP किसी के साथ साझा न करें। वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी बनकर धमकाने वालों से सावधान रहें। किसी भी साइबर फ्रॉड की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

(ये रहे मौजूद)

इस सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी निरीक्षक केदार सिंह यादव के साथ उनि छाया राय, सउनि रामसिंह भिलाला, आरक्षक अनूप कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम ने पंपलेट वितरित कर एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया।

(क्या है सेफ क्लिक 2.0?)

'ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0' मध्य प्रदेश पुलिस का प्रदेशव्यापी अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना, अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई करना तथा आमजन को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक कर साइबर ठगी से बचाना है।

राजस्थान में मुस्लिम समुदाय के समर्थन में सड़क पर उतरे लाखों हिंदू भाई

राजस्थान के बाड़मेर में एक मस्जिद को प्रशासन के बुलडोजर ने ढहा दिया। इसके विरोध में सभी जाति धर्म के लोग रैली निकाल रहे हैं। कमाल की बात यह है इस रैली में 80 पर्सेंट लोग हिंदू समुदाय से हैं। आज तक आपने ऐसी रैली नहीं देखी होगी जिसमें मस्जिद के समर्थन में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग इस तरह खुलकर सड़क पर आ गए हों। देश की तरक्की के लिए विभाजन कारी तत्वों से बचने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है।

अमेरिका और ईरान, होर्मुज जलडमरूमध्य विवाद पर आज अहम वार्ता

दोहा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान आज कतर की राजधानी दोहा में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर जारी विवाद पर महत्वपूर्ण वार्ता करेंगे।

इस बातचीत का उद्देश्य क्षेत्र में तनाव कम करना, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे असर को कम करना है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार, वार्ता में समुद्री जहाजों की सुरक्षित आवाजाही, क्षेत्रीय सुरक्षा, तनाव कम करने के उपाय और भविष्य में किसी भी टकराव से बचने के लिए विश्वास बहाली के कदमों पर चर्चा होने की संभावना है। कतर इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है।

प्रतिभा का सम्मान ही राष्ट्र निर्माण की नींव: बामौर कलां में डीआरएस कोचिंग का भव्य प्रतिभा एवं कला सम्मान समारोह सम्पन्न

अतुल जैन

22 विद्यार्थियों को लैपटॉप, 2 छात्राओं को स्कूटी प्राप्त होने पर किया सम्मानित, कक्षा 10वीं के टॉपर्स व बुंदेली कलाकारों का भी हुआ अभिनंदन

खनियांधाना। शिक्षा, प्रतिभा और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से डीआरएस कोचिंग, बामौर कलां द्वारा मंगलवार को मांगलिक भवन में "प्रतिभा एवं कला सम्मान समारोह" का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, पुलिस, राजस्व, मीडिया एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने आयोजन को गरिमामयी बना दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थाना प्रभारी संजय लोधी रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शासन की योजना के अंतर्गत 22 विद्यार्थियों को लैपटॉप तथा 2 छात्राओं को स्कूटी प्राप्त होने पर विशेष सम्मान किया गया। इसके अलावा कक्षा 10वीं के विद्यालय एवं परीक्षा केंद्र के टॉपर विद्यार्थियों

को भी सम्मानित कर उनके उज्वल भविष्य की कामना की गई।

समारोह के दौरान बुंदेली लोककला एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रसिद्ध कलाकार हरनाम नरवरिया एवं देशराज नरवरिया का भी विशेष सम्मान किया गया। आयोजकों ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ अपनी लोक संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों का सम्मान समाज को नई दिशा देता है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों का भी सम्मान किया गया। आयोजकों ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी की सफलता के पीछे माता-पिता का त्याग, मार्गदर्शन और शिक्षकों का सतत प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्रतिभाओं के साथ-साथ उनके प्रेरणास्रोत अभिभावकों का सम्मान भी आवश्यक है।

अपने प्रेरणादायी संबोधन में मुख्य अतिथि थाना प्रभारी संजय लोधी ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी की सफलता केवल उसके व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसके माता-पिता और शिक्षकों की मेहनत एवं मार्गदर्शन भी उसमें बराबर की भागीदारी निभाते हैं। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई में लगातार सहयोग और प्रोत्साहन देते रहें ताकि वे जीवन में नई ऊँचाइयों तक पहुँच सकें। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता मिलने के बाद रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर बार स्वयं का नया लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी ने 80 या 90 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं तो अगली बार उसका लक्ष्य 100 प्रतिशत होना चाहिए। जब लक्ष्य बड़ा होगा, तभी उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्य 100 अंक होगा तो विद्यार्थी निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करेगा और समाज व देश का नाम रोशन करेगा।

संजय लोधी ने कहा कि शासन द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप एवं स्कूटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना केवल पुरस्कार नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा है। इन योजनाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आधुनिक संसाधनों से जोड़ना है। उन्होंने विद्यार्थियों से मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। समारोह में शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, मीडिया जगत, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की उपस्थिति रही। पूरे कार्यक्रम के दौरान मेधावी विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था और सम्मान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शिक्षा, प्रतिभा, कला और संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना तथा मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। समारोह का सफल संचालन एवं आयोजन डीआरएस कोचिंग, बामौर कलां द्वारा किया गया। अंत में सभी अतिथियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायी आयोजनों को निरंतर आयोजित करने का संकल्प लिया गया।

दिल्ली में 18 करोड़ का बैंक लोन घोटाला: 9 साल से फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार

रणजीत टाइम्स

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 9 वर्षों से फरार घोषित अपराधी संजीव दीक्षित उर्फ संजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।

जांच के अनुसार,

आरोपी ने एक विधवा मकान मालकिन के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी संपत्ति को गिरवी दिखाते हुए विभिन्न बैंकों से 18 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण हासिल किया। इस धोखाधड़ी में असली संपत्ति मालिक और बैंक दोनों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।

पुलिस के अनुसार

आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार पहचान बदलता रहा। जांच के दौरान पता चला कि वह दूसरे नाम से तिहाड़ जेल में बंद था, जहां से उसे इस मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।

आर्थिक अपराध शाखा अब इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों, दस्तावेज तैयार करने वालों और संभावित बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

बेटे-बहू से परेशान वृद्ध महिला को पुलिस ने दिलाई राहत

जनसुनवाई में शिकायत के बाद जूनी इंदौर पुलिस ने कराया पारिवारिक विवाद का समाधान

राजेश धाकड़

इंदौर। पुलिस आयुक्त इंदौर की जनसुनवाई में पहुंची 70 वर्षीय वृद्ध महिला की शिकायत पर जूनी इंदौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे राहत दिलाई।

जूनी इंदौर निवासी तुलसीबाई पति रामसिंह ने शिकायत की थी कि बेटे-बहू द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और घर में रखने से मना करते हुए डराया-धमकाया जा रहा है।मामले को गंभीरता

से लेते हुए पुलिस आयुक्त के निर्देश पर थाना जूनी इंदौर पुलिस टीम ने परिवार के सदस्यों से चर्चा की। पुलिस ने वृद्ध महिला के सम्मान, देखभाल और भरण-पोषण की जिम्मेदारियों के संबंध में समझाइश दी।

पुलिस की पहल के बाद परिवार के बीच आपसी सहमति बनी और वृद्ध महिला की देखभाल करने का आश्वासन दिया गया। पुलिस ने शिकायत का निराकरण कर वृद्ध महिला को राहत पहुंचाई।

मांगलिया चौकी प्रभारी सतेंद्र सिंह सिसोदिया से सह-संपादक दीपक वाडेकर की शिष्टाचार भेंट

रणजीत टाइम्स के सह-संपादक दीपक वाडेकर ने मांगलिया चौकी के नवनियुक्त प्रभारी श्री सतेंद्र सिंह सिसोदिया से

शिष्टाचार भेंट कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर दीपक वाडेकर ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री सिसोदिया के नेतृत्व में मांगलिया क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा आमजन को बेहतर पुलिस सेवाएँ प्राप्त होंगी। दोनों के बीच क्षेत्र की सुरक्षा, जनसहयोग और सामाजिक समन्वय जैसे विषयों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। रणजीत टाइम्स परिवार की ओर से श्री सतेंद्र सिंह सिसोदिया को नई जिम्मेदारी हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

मानसून अवधि में जिले की सभी रेत खदानों में खनन गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

हेमंत कुमार भार्गव

शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जिले की समस्त रेत खदानों में मानसून अवधि के दौरान खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश-2016 तथा रेत खनन के लिए प्रवर्तन एवं निगरानी दिशा-निर्देश-2020 के प्रावधानों के पालन में यह निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर तक जिले की सभी रेत खदानों में खनन संबंधी समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। यह निर्णय मानसून के दौरान पर्यावरण संरक्षण तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

प्रशासन की कार्यवाही, करैरा में शासकीय भूमि कराई अतिक्रमणमुक्त

हाईवे स्थित सिरसौद चौराहे पर अवैध निर्माण हटाया गया

हेमंत भार्गव

शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार करैरा में प्रशासन की टीम ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। अनुविभागीय दंडाधिकारी करैरा श्री अनुपम शर्मा एवं तहसीलदार श्री ललित शर्मा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हाईवे स्थित सिरसौद चौराहे की करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराकर शासन के कब्जे में लिया तथा ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया। तहसील करैरा अंतर्गत ग्राम पंचायत घसारही के सर्वे क्रमांक 177, रकबा 1.50 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर दो व्यक्तियों द्वारा सीमेंट के पिलर लगाकर फेंसिंग कर अवैध कब्जा किए

जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत मिलते ही एसडीएम एवं तहसीलदार राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को हटाते हुए भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद चौकीदार ने निर्माण कार्य को सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाना बताया गया। प्रशासन ने तत्काल सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की, जिन्होंने किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराए जाने से स्पष्ट इनकार किया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जा हटाकर शासकीय भूमि को अपने कब्जे में लिया तथा स्थल पर सूचना पटल भी स्थापित कराया। एसडीएम श्री अनुपम शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

वैल्यू चेन क्लस्टर योजना के तहत 300 किसानों को निःशुल्क मूंगफली बीज का वितरण

हेमंत भार्गव

करैरा। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से

मंगलवार को मृदा परीक्षण केंद्र, टीला रोड पर वैल्यू चेन क्लस्टर योजना के अंतर्गत किसानों को निःशुल्क मूंगफली बीज वितरित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 300 किसानों को मूंगफली का बीज उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर करेरा की क्षेत्रीय विधायक रमेश प्रसाद खटीक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 400 क्विंटल मूंगफली बीज प्राप्त हो चुका है, जबकि लगभग 1600 क्विंटल बीज और प्राप्त होना शेष है। जैसे-जैसे बीज उपलब्ध होगा, पात्र किसानों को उसका निःशुल्क वितरण लगातार किया जाता रहेगा। कार्यक्रम में किसानों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा वैज्ञानिक खेती अपनाने की अपील की गई। इस दौरान भाजपा नेता पवन निगोती, कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।